



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2003/श्रावण 15, 1925

No. 708 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2003/SRAVANA 15, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2003

का.आ. 907(अ).—केंद्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब वक्फ बोर्ड के साथ परामर्श से और उस पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा दी गई सहमति से, उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों का समावेश करते हुए, उसके द्वारा गठित पंजाब वक्फ बोर्ड के, अगस्त, 2003 से, विभाजन का अनुमोदन करती है और निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को लागू करती है, अर्थात् :-

(क) विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड 1 अगस्त, 2003 को भंग हो जाएगा और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 और धारा 14 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार एक साथ अपने अपने राज्य वक्फ बोर्डों का गठन करेंगे और इस प्रकार गठित बोर्डों की पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आने वाले अपने क्षेत्रों में अधिकारिता होगी ।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार, केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन करेगी जिसकी संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी ।

(ग) घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन और उसकी आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का प्रभाजन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा, अर्थात् :-

### 1. आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन:-

1.1 उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड, वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड को मिलने वाले लाभों को प्राप्त करेंगे और उसके वित्तीय दायित्वों का भी वहन करेंगे ।

1.2 आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों में आस्तियों और दायित्वों के उचित, साम्यापूर्ण और युक्तियुक्त प्रभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

1.3 वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम से संबंधित किसी भी विवाद का निपटान संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा जिसमें असफल रहने पर मामले में केंद्रीय सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा ।

### 2. स्थिर आस्तियां :-

2.1 चूंकि पंजाब वक्फ बोर्ड की स्थिर आस्तियां पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के क्षेत्रों में फैली हुई हैं, “जैसा है जहां है” का सिद्धांत उन संपत्तियों, भूमि तथा भवनों, वृक्षों और बगीचों तथा अन्य विन्यासों के संबंध में अपनाया जाएगा और उनसे संबंधित अभिलेख जैसे, फाइलें, राजपत्र अधिसूचनाएं, सर्वेक्षण रजिस्टर, किताबुल औकफ तथा अभिधृति नक्शे और फाइलें उस संबंधित वक्फ बोर्ड को जाएंगी जहां वह संपत्ति स्थित है ।

2.2 पंजाब वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी अन्य स्टोर सामान, वस्तुएं और अन्य माल उस उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति होंगी जिसके क्षेत्र में ऐसे स्टोर सामान वस्तुएं और अन्य माल स्थित हैं ।

2.3 यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई माल या माल के वर्ग का वितरण वस्तुओं की अवस्थिति के अनुसार से भिन्न उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों के बीच किया जाना अपेक्षित है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो माल के न्यायोचित और साम्यापूर्ण वितरण के लिए उचित समझती है और वे माल तदनुसार उत्तराधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों को संक्रान्त हो जाएंगे ।

2.4 पंजाब वक्फ बोर्ड के मुख्यालयों से संबंधित सभी स्टोर सामान संघटक राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र के बीच होने वाली सहमति के अनुसार विभाजित होंगे और ऐसे करार का व्यतिक्रम होने पर ऐसे स्टोर सामान के न्यायोचित तथा साम्यापूर्ण वितरण के लिए जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दें, विभाजित होंगे ।

### 3. बैंक अतिशेष तथा सावधि जमा :-

चूंकि पंजाब वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध बैंक अतिशेष और सावधि जमा सामान्य पूल आय से प्राप्त हुई है, अतः, तारीख 1 अगस्त, 2001 को विद्यमान बैंक अतिशेष तथा सावधि जमाओं को संघटक राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया जाएगा, जो संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के लिए न्यूनतम 2% तथा हिमाचल प्रदेश के लिए 5% के अध्वधीन होगा । यह इस राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में वक्फ संपत्तियों की संख्या तथा क्षेत्र की न्यूनता की दृष्टि से होगा ।

अतः अनुपात इस प्रकार होगा:

पंजाब	61 %
हरियाणा	32 %
हिमाचल प्रदेश	5 %
चंडीगढ़	2 %

### 4. दायित्व :-

मलेर कोटला में एचजेड हलीमा महिला अस्तपताल के निर्माण के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली से वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण का दायित्व केवल पंजाब राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी पंजाब राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा मोचन किया जाएगा ।

### 5. कर्मचारिवृन्द का प्रभाजन:-

5.1 मुख्यालय कर्मचारिवृन्द अम्बाला में पंजाब वक्फ बोर्ड के मुख्यालय के कर्मचारियों का विभाजन प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए क्रमशः 5 % तथा 2 % की दर से न्यूनतम कर्मचारिवृन्द के अधीन वक्फ संपत्तियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा । अतः, मुख्यालय कर्मचारिवृन्द का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा:

पंजाब	61 %
हरियाणा	32 %
हिमाचल प्रदेश	5 %
चंडीगढ़	2 %

5.2 क्षेत्र कर्मचारिवृन्द विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवारत क्षेत्रीय कर्मचारिवृन्द सामान्य तौर पर उस राज्य वक्फ बोर्ड के होंगे जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में विभाजन के पश्चात् उसका कार्यालय है।

5.3 (क) मुख्यालय के कर्मचारिवृन्द के विभाजन तथा उन कर्मचारिवृन्द के अभ्यावेदनों पर विनिश्चय के लिए जो उपरोक्त के अनुसार बने रहना नहीं चाहते हैं, यथाविनिर्दिष्ट पंजाब वक्फ बोर्ड के विद्यमान प्रशासक श्री एम0 रहमान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और यह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी तथा वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रशासन अधिकारी (मानव संसाधन विकास) से मिलकर बनेगा।

(ख) यह समिति ऐसे मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारिवृन्द से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उनकी रुचि का विकल्प मांगेगी तथा उनके निवास स्थान, सेवा अवधि और सेवा के वर्ग आदि को ध्यान में रखते हुए प्रभाजन के लिए सिद्धांत बनाएगी।

(ग) इस समिति की सिफारिशों को इस आदेश के पैरा (ग) के उप - पैरा 7 के अनुसार गठित संचालन समिति को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) कर्मचारिवृन्द के प्रभाजन, उस पर इसकी सिफारिशों तथा उस पर संचालन समिति की सहमति से संबंधित समिति का कार्य इस आदेश की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(ङ) यदि संचालन समिति किसी बात पर सहमत नहीं होती है तो केंद्रीय सरकार इस संबंध में विनिश्चय करेगी जो सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा उत्तरवर्ती राज्य वक्फ बोर्डों पर बाध्यकारी होगा।

5.4 प्रत्येक व्यक्ति जो विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकलाप के संबंध में कोई पद धारण कर रहा है या कार्यालय के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, वह उस उत्तरवर्ती राज्य

वक्फ बोर्ड में उसी पद या कार्यालय में बना रहेगा और उसी पद पर या कार्यालय में सम्बद्ध राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

### 5.5 कर्मचारीवृन्द के ऋणों और अग्रिमों की वसूली:

जिन कर्मचारिवृन्द ने विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड से ऋण और अग्रिम लिए हैं वे उसके समापन तक उस उत्तरवर्ती वक्फ बोर्ड को किश्तें देते रहेंगे जिसके लिए उन्हें आबंटित किया गया है ।

### 6. संविदाएं :-

जहां, विभाजन की नियत तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 2003 से विद्यमान वक्फ बोर्ड ने बोर्ड के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की है, वह उस उत्तरवर्ती राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा की गई मानी जाएगी जिससे वह संविदा संबंधित है और सभी अधिकार तथा दायित्व जो प्रोद्भूत हुए हैं या जो किसी ऐसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हो सकेंगे, वे उत्तरवर्ती राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकार एवं दायित्व हो जाएंगे ।

### 7. संचालन समिति :-

(क) इस आदेश के प्रयोजनों को प्रभाव में लाने के लिए विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रशासक श्री एम0 रहमान की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की जाती है ।

(ख) इस समिति में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्य सचिवों के नामनिर्देशिती होंगे और यह इस आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन की स्कीम को पूर्ण करेगी ।

(ग) श्री रहमान विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यालय से वही मानदेय और वही सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जो अब तक प्राप्त कर रहे थे और इस समिति को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उत्तरवर्ती राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा सभी सहायता प्रदान की जाएगी ।

(घ) विद्यमान पंजाब वक्फ बोर्ड के विद्यमान बैंक खाते को, इस आदेश के अनुसार उसमें पड़ी हुई धनराशि के विभाजन को प्रभाव में लाने के प्रयोजनार्थ पहले की भांति श्री रहमान द्वारा चलाया जाएगा ।

**8. अवशिष्ट प्रावधानः**

केन्द्रीय सरकार उस किसी भी मुद्दे के बारे में विनिश्चय करेगी जिसके संबंध में संघटक राज्य सरकारें तथ संघ राज्य क्षेत्र समझौता नहीं कर पाते हैं और केन्द्रीय सरकार का ऐसा निर्णय बाध्यकारी होगा।

[फा. सं. 4(4)/2000-वक्फ-खंड II]

सपना राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****ORDER**

New Delhi, the 29th July, 2003

**S.O. 907(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 102 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby approves the scheme of division of the Punjab Wakf Board, framed by it in consultation with the Punjab Wakf Board and consented to by the State Governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh, incorporating the modifications suggested by them with effect from the 1<sup>st</sup> day of August 2003, and gives effect to the scheme so approved by making the following order, namely:—

- (A) The existing Punjab Wakf Board shall be dissolved on the 1<sup>st</sup> day of August 2003 and the State Governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh shall simultaneously constitute their own State Wakf Boards as per the provisions contained in sections 13 and 14 of the Wakf Act, 1995 and the Boards so constituted shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.
- (B) The Central Government shall constitute a Wakf Board for the Union territory of Chandigarh, which shall have jurisdiction over the areas falling in the Union territory of Chandigarh, as per the provisions contained in sub-section (7) of section 14 of the said Act;
- (C) The following principles shall govern the division of the Punjab Wakf Board and apportionment of its assets, liabilities and staff amongst the constituent States and the Union territory of Chandigarh, namely:—

**1. Apportionment of Assets and Liabilities:**

1.1 The successor State Wakf Boards shall receive the benefits as also bear the financial liabilities of the existing Punjab Wakf Board.

1.2 The apportionment of assets and liabilities shall be subject to such financial adjustment as may be necessary to secure a just, equitable and reasonable apportionment of the assets and liabilities amongst the successor State Wakf Boards.

1.3 Any dispute regarding the amount of financial assets and liabilities shall be settled through mutual agreement amongst the concerned States and the Union territory failing which the decision of the Central Government in the matter shall be binding.

**2. Fixed Assets**

2.1 As the fixed assets of the Punjab Wakf Board are spread all over the areas of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh, the principle of 'as is where is' shall be adopted in respect of the properties, land and buildings, trees and orchards and other endowments and records pertaining thereto like files, Gazette notifications, survey registers, kitabul aukaf and tenancy maps and files will go to the concerned State Wakf Board where that property is situated.

2.2 All other stores, articles and other goods belonging to the Punjab Wakf Board shall become the property of the successor State Wakf Board in whose territory such stores, articles and other goods are situated.

2.3 If the Central Government is of the opinion that any goods or class of goods requires to be distributed between the successor State Wakf Boards otherwise than according to the situation of the goods, the Central Government may issue such directions as it thinks fit for a just and equitable distribution of the goods and those goods shall pass on to the successor State Wakf Boards accordingly.

2.4 All stores relating to the Headquarters office of the Punjab Wakf Board shall be divided as may be agreed upon amongst the constituent States and the Union territory and in default of such agreement, as the Central Government may direct for a just and equitable distribution of such stores.

### **3. Bank Balance and Fixed Deposits**

As the bank balance and fixed deposits available with the Punjab Wakf Board have come from the common pool income, the bank balance and fixed deposits existing as on the 1<sup>st</sup> August, 2003 shall be divided on the basis of the percentage of wakf properties existing in the constituent States and the Union territory, subject to a minimum of 2% for the Union territory of Chandigarh and 5% for Himachal Pradesh, in view of the smallness of the area and the number of wakf properties in this State and the Union territory. The ratio shall, therefore, be:

Punjab	-	61%
Haryana	-	32%
Himachal Pradesh	-	5%
Chandigarh	-	2%

### **4. Liabilities**

As the liability of the loan raised by the existing Punjab Wakf Board from the Central Wakf Council, New Delhi for construction of Hz. Halima Women Hospital at Malerkotla relates only to Punjab State, it will be entirely redeemed by the successor Punjab State Wakf Board.

### **5. Apportionment of Staff:**

5.1 Headquarter Staff: The staff of the Headquarters of the Punjab Wakf Board at Ambala shall be divided on the basis of the number of wakf properties in each State and the Union territory, subject to a minimum staff for Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh at the rate of 5% and



2% respectively. The Headquarters staff shall, therefore, be apportioned as follows:

Punjab	-	61%
Haryana	-	32%
H.P.	-	5%
Chandigarh	-	2%

5.2 Field Staff: The field staff serving in the field offices of the existing Punjab Wakf Board shall normally belong to the State Wakf Board in whose area of jurisdiction that office is situated after division.

5.3(a) For deciding the division of Head Office staff and representations of field staff who do not wish to continue as specified above, a Committee is hereby constituted under the Chairmanship of Shri M.Rehman, Administrator of the existing Punjab Wakf Board and will consist of the Chief Executive Officer, Senior Law Officer and Administrative Officer (Human Resources Development) of the existing Punjab Wakf Board.

(b) This Committee will take options from such Headquarters and field staff about their choice of State or the Union territory and will devise principles for apportionment keeping in view the domicile, length of service, class of service etc.

(c) The recommendations of this Committee shall be submitted to the Steering Committee constituted as per sub-paragraph 7 of paragraph (C) of this Order for its consent.

(d) The work of the Committee relating to apportionment of staff, its recommendations thereon and consent of the Steering Committee thereto shall be completed within a period of 60 days from the date of this Order.

(e) If the Steering Committee fails to agree on any point, then the Central Government shall take a decision in this regard which shall be binding on all the States and the Union territory of Chandigarh and the successor State Wakf Boards.

5.4 Every person holding or discharging the duties of any post or office in connection with the affairs of the existing Punjab Wakf Board shall continue to hold the same post or the office in that successor State Wakf Board and shall be deemed to have been duly appointed to that post or the office by the concerned State Wakf Board.

**5.5 Recovery of loans and Advances against Staff:**

The employees who have taken loans and advances from the existing Punjab Wakf Board shall continue to pay the instalments until liquidation thereof to the successor State Wakf Board to which they are allocated.

**6. Contracts**

Where, before the appointed date of division, i.e., the 1<sup>st</sup> day of August, 2003, the existing Punjab Wakf Board has made any contract for the purposes of the Board, that contract shall be deemed to have been made by the successor State Wakf Board to which the contract relates and all the rights and liabilities which have accrued, or which may accrue under any such contract, shall be the rights and liabilities of the successor State Wakf Boards.

**7. Steering Committee**

(a) A steering Committee headed by Shri M. Rehman, Administrator of the existing Punjab Wakf Board is hereby constituted to give effect to the purposes of this Order.

(b) This Committee shall consist of the nominees of the Chief Secretaries of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh and shall complete the scheme of division of the existing Punjab Wakf Board within a period of three months from the date of this Order.

(c) Shri Rehman shall continue to derive the same honorarium and facilities from the office of the existing Punjab Wakf Board as hitherto and all assistance shall be provided by the

successor State Wakf Boards to this Committee to accomplish its objectives.

(d) The bank accounts of the existing Punjab Wakf Board shall be operated by Shri Rehman as before for the purpose of effecting a division of the moneys lying therein as per this Order.

**8. Residuary Provisions:**

The Central Government shall decide any issue in respect of which the constituent State Governments and the Union territory Administration fail to reach an agreement and such decision of the Central Government shall be binding.

[F. No. 4(4)/2000-Wakf-Vol. II]

SWAPNA RAY, Jt. Secy.